पोलैंड की दूसरी सबसे बड़ी नदी ओडर में एक छोटा सा टापू है। गल्स, टर्न और प्लोवर जैसी कई पक्षी प्रजातियां यहां प्रजनन करती हैं। लेकिन रोचक बात है कि, यह एक कृत्रिम द्वीप है। वन्यजीव फोटोग्राफर और पर्यावरणविद् प्योत्र चारा ने खुद ऐसे 8 कृत्रिम टापू बनाए हैं। चारा का कहना है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, प्राकृतिक या अर्धप्राकृतिक टापुओं पर पक्षियों के अधिकांश बच्चों को रकून व अमेरिकन मिंक (एक प्रकार का ऊद बिलाव) जैसे बाहरी परभक्षी खा जाते थे। मूलतः उत्तरी अमेरिका में मिलने वाले ये परभक्षी कुछ समय से उत्तर पश्चिमी पोलैण्ड सहित यूरोप के कई भागों में बहुत आक्रामक हो गए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, 18 वीं और 19 वीं सदी में, जब ओडर नदी का निचला भाग जर्मनी का हिस्सा था, उस समय, हर साल आने वाली बाढ़ को रोकने, जहाजों के परिवहन और नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए नदी के साथ -साथ छोटे-छोटे तटबंध बनाए गए थे। इस निर्माण कार्य के कारण नदी के प्राकृतिक रेतीले टापू नष्ट हो गए, जहाँ हजारों की संख्या में जलीय पक्षी घोंसले बनाते थे। बाध्य होकर कई जानवरों को अन्यत्र जाना पड़ा। लेकिन ओडर नदी के एक तिहाई निचले हिस्से, करीब 45 कि.मी., में तटबंध नहीं थे इसलिए यहाँ पक्षी खूब फले फूले। सन् 2001 में चारा जब पहली बार यहां आए तब यहां की बची हुई पक्षी विविधता देखकर दंग रह गए। नब्बे के दशक तक उत्तरी पोलैंड की हर झील में यूरेशियन कूट्स पक्षी दिखाई देते थे पर मिंक के आने के बाद कई झीलों से ये पक्षी लुप्त हो गए। नब्बे के दशक के मध्य में पोलैंड में गल्स के 4300 जोड़े थे, पर, वर्ष 2009 तक मिंक्स के कारण ये घटकर मात्र 2300 ही रह गए। रकून की घुसपैठ जर्मनी से हुई थी। इन परभक्षियों के विनाशकारी प्रभाव को देखने के बाद चारा ने सेना की बेकार पड़ी नौकाओं में मिट्टी भरकर कृत्रिम टापू बनाने शुरु किए। पहला टापू 2015 में बना। नौकाओं के किनारों पर धातु की परत चढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से मिंक व रकून इन पर नहीं चढ़ पाते थे। उसी वर्ष यूरेशियन ऑयस्टर कैचर के एक जोड़े ने पहली बार कृत्रिम टापू पर घोंसला बनाया, फिर कुछ ही सप्ताह में कई दर्जन घोंसले बन गए। उसी साल के अंत तक चारा ने दो और टापू बनाए और 2017 में 5 टापू बनाए, जिन पर अब पक्षी फल-फूल रहे हैं।

''राईट-टू हैल्थ'' बिल पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर किए

डॉक्टरों के संगठनों ने कहा कि, अगर इस विधेयक में वे शर्तें शामिल नहीं की गईं, जिन पर डॉक्टरों और सरकार का समझौता हुआ था, तो डॉक्टर अपने अस्पतालों में किसी भी सरकारी प्रोग्राम व योजना को शामिल नहीं करेंगे

-यादवेंद्र शर्मा-

जयपुर, 12 अप्रेल। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा के अष्टम सत्र में 21 मार्च 2023 को पारित ''राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022'' को अनुमति प्रदान कर दी है। इस विधेयक के पारित होने से डॉक्टरों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जैसा कि विदित है कि डॉक्टर ''राइट टू हैल्थ'' (आर.टी.एच.) बिल को लागू करने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और 4 अप्रेल को लाखों की तादाद में डॉक्टर्स ने जयपुर की सड़कों पर भी आंदोलन किया था।

आर.टी.एच बिल पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर करने पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉक्टर विजय कपूर ने ट्वीट किया कि ''माननीय राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर के पश्चात राजस्थान सरकार द्वारा आर.टी.एच बिल में एम.ओ.यू. के तहत हुए समझौते को अक्षरशः लागू किए जाने की आशा व अपेक्षा है। ऐसा न होने की सूरत में समस्त प्रदेश के सरकारी योजनाओं का पूर्ण बहिष्कार किया जाना प्रस्तावित है।''

> ■ **प्राइवेट हॉस्पीटल एण्ड नर्सिंग होम्स सोसायटी के सचिव डॉ. विजय कपूर ने कहा कि उन्हें इस नवीनतम घटनाक्रम की पूरी जानकारी है तथा वे और उनका संगठन सही समय आने पर आर.टी.एच. कानून को अदालत में चुनौती देंगे।**

उल्लेखनीय है कि 4 अप्रेल को हुए प्रदर्शन के दौरान ही डॉक्टर विजय कपूर ने सभी डॉक्टरों को सूचना दी थी कि डॉक्टरों की संयुक्त एक्शन कमेटी के प्रतिनिधि जिनमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम सोसायटी के प्रतिनिधि और उपचार यानि युनाइटेड प्राइवेट क्लिनिक एंड हॉस्पिटल एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के प्रतिनिधि शामिल थे द्वारा मीडिया को यह बताया गया कि छोटे प्राईवेट अस्पताल जिन्हें सरकार से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, उन पर आर.टी.एच. लागू नही होगा। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में करीब 4100 छोटे प्राईवेट अस्पतालों को आर.टी.एच.से बाहर करने के लिये राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव (चिकित्सा शिक्षा) ने डॉक्टरों की कमेटी के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टेंडिंग (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित किया था। हालांकि कई बड़े प्राईवेट अस्पतालों की तरफ से भी कहा जा रहा था कि उन पर आर.टी.एच. इसलिये लागू नहीं होगा क्योंकि उन पर केवल अस्पताल निर्माण के लिये दी गई जमीन पर लगाई गई शर्तें ही लागू होंगी, जिसके अनुसार उन्हें अस्पताल में कुल बैड का कुछ प्रतिशत सरकार द्वारा पारिभाषित गरीबी रेखा के नीचे आने वाले मरीजों के लिये आरक्षित रखना होगा।

पर कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 299 के अनुसार राज्य व केंद्र सरकार पर केवल वहीं अनुबंधन लागू किये जा सकते हैं जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम पर ही हस्ताक्षरित हों।

दूसरी ओर राज्य सरकार ने डॉक्टरों के साथ हुई बातचीत और सहमति पत्र को लागू करने के लिये आर.टी.एच. बिल को राज्यपाल को पत्र लिखकर वापस बुलाने, या संशोधन करने की ओर कोई कदम नहीं उठाये, इसलिये राज्यपाल द्वारा इस बिल को पारित करना एक सामान्य और संवैधानिक प्रक्रिया है। वहीं कानूनी विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि चूंकि अब यह विधेयक कानून बन चुका है, इसलिए इसके प्रावधानों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्थान हाईकोर्ट में प्राईवेट डॉक्टरों की हड़ताल को गैर कानूनी घोषित करने के संबंध में दायर जनहित याचिका बुधवार को ही सुनवाई के लिये सूचीबद्ध थी, क्योंकि राज्य सरकार ने कल छुट्टी घोषित कर दी थी। इस मामले में अदालत ने महाधिवक्ता को कहा था कि वे राज्य सरकार और डॉक्टरों के बीच हुई विभिन्न मीटिंगों का विस्तृत ब्यौरा पेश करें ताकि ये समझा जा सके कि डॉक्टर आखिर क्यों हड़ताल पर हैं। परंतु अदालत के समक्ष छोटे अस्पतालों या बड़े अस्पतालों की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व प्रस्तुत नहीं किया गया।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि निजी डॉक्टरों और राज्य सरकार के बीच समझौता हो चुका है और निजी चिकित्सकों ने अपनी हड़ताल वापिस ले ली है।

इस तथ्य को रिकॉर्ड पर लेते हुए खंडपीठ ने जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया।

प्राइवेट हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स सोसायटी सचिव डॉ.विजय कपूर ने कहा कि उन्हें इस मामले के नवीनतम घटनाक्रम की पूरी जानकारी है और वे और उनका संगठन आर.टी.एच. विधेयक को अदालत में सही समय पर चुनौती देंगे।

वहीं बड़े अस्पतालों की ओर से भी कई डॉक्टरों ने कहा कि वे सही समय पर स्वतंत्र रूप से आर.टी.एच. विधेयक को गैर कानूनी घोषित करने के लिये याचिका दायर करेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने आर.टी.एच.बिल को लागू करने के लिये कोष भी निर्धारित नही किया है और ना ही नियम-कायदों का गठन किया है।

'क्या कोलीजियम की सिफारिशें आर.टी.आई. के दायरे में हैं?'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 अप्रेल। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट (2005) के तहत सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम की सिफारिशों की जानकारी मांगे जाने की याचिकाओं पर केन्द्र सरकार से उसकी प्रतिक्रिया देने को कहा है।

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा से कहा है कि इस मामले पर उपयुक्त निर्देश प्राप्त करें और हलफनामा दायर करे मामले की सुनवाई मई में होगी।

कोर्ट तीन याचिकाओं की सम्मिलित रुप से सुनवाी कर रहा है कि क्या कोलीजियम की सिफारिशों को आर.टी.आई. एक्ट के तहत बताया जा सकता है। एक याचिका किसी डॉ. विनोद सुराणा ने दायर की है, जो जानना चाहते थे कि 1990 और 1992 के बीच तत्कालीन सी जे आई ओर मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनके पिता पी.एस. सुराणा के मद्रास हाईकोर्ट में बतौर जज पदोन्नयन पर क्या सिफारिश की थी।

> ■ **दिल्ली हाई कोर्ट ने आर.टी.आई. कानून के तहत, सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम की सिफारिशों की जानकारी मांगे जाने पर केन्द्र से राय मांगी है।**

सुराणा ने सिफारिश से संबंधित पूरे दस्तावेजों, रिकॉर्ड और फाइल नोसि की प्रमाणित प्रतियां और सिफारिशों पर आगे न ही बढ़ने के कारणों को दर्ज करने वाले दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मांगी। सुप्रीम कोर्ट के पी.आई.ओ. ने जानकारी देने से मना कर दिया।

अन्य दो याचिकाएं एक ऐसे मामले में दायर क्रॉस अपीलें है जिसमें किसी दिनेश कुमार मिश्रा ने 2008 में गुवादारी उच्च न्यायालय में दो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जानकारी मांगी है।

इंगलैण्ड के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की टिप्पणियों को नस्लीय, अस्वीकार्य, भड़काऊ और विभाजनकारी माना गया है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म चेंज, ओ.आर. जी. पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 28 हजार लोगों के हस्ताक्षर हैं। इन लोगों ने सुएला ब्रेवरमन की बेलगाम और अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर उन्हें तुरन्त प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की है।

जैसा कि मीडिया को बताया गया, ब्रेवरमन की टिप्पणियों से सामुदायिक एकता के समाप्त होने और नस्लीय तनाव बढ़ने का खतरा है।

प्रधानमंत्री आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि सरकार की मंत्री होने के नाते उन पर सभी समुदायों के लिए धैर्य व आदरभाव बढ़ाने की जिम्मेवारी थी, लेकिन उनकी टिप्पणियां स्तरहीन हैं। किसी जन नेता की ऐसी अपमानजनक टिप्पणियों अस्वीकार्य हैं, जिनसे किसी पूरे समुदाय पर तोहमत लगती हो।

पत्र में कहा गया है कि, इस मुद्दे को संबोधित करने तथा सहिष्णुता, आदर व निष्पक्षता के मूल्यों को कायम रखने के लिए तत्परता से निर्णायक कार्रवाई की जाए। क्योंकि ये एक सामन्जस्यपूर्ण समाज के लिए आवश्यक है।

प्रधानमंत्री सुनक को लिए एक खुले पत्र में ब्रिटिश पाकिस्तानी फाउण्डेशन के 18,000 सदस्यों ने, गृह मंत्री की हालिया टिप्पणियों पर तथा प्रधानमंत्री द्वारा टिप्पणियों के खिलाफ नहीं बोलने पर अपनी गहरी चिंता व निराशा व्यक्त की है।

इन टिप्पणियों में, तथाकथित ''गूमिश गैंग्स'' ब्रिटिश पाकिस्तानियों की संलिप्तता तथा ''ब्रिटिश मूल्यों'' के बिल्कुल खिलाफ ''सांस्कृतिक मूल्यों'' के होने की बात कही है।

''जिस विभाजक एवं खतरनाक तरीके से होम सैक्रेटरी सभी ब्रिटिश पाकिस्तानी पुरुषों को दर्शाने का प्रयास कर रही हैं तथा यह संकेत दे रही हैं कि इन पुरुषों के क्रियाकलापों में समुदाय की भी मिलीभगत है, वो बहुत निन्दनीय है।''

भटिंडा के मिलिटरी स्टेशन में फायरिंग, सेना के चार जवानों की मौत

चंडीगढ़, 12 अप्रेल। पंजाब के बठिंडा मिलिटरी स्टेशन में बुधवार सुबह हुई फायरिंग में सेना के 4 जवानों की मौत हो गई। 80 मीडियम रेजिमेंट के ये जवान ऑफिसर्स मेस में गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे। आर्मी ने कहा कि, फायरिंग सुबह 4:35 बजे हुई। 4 मौतों के अलावा जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस और सेना की टीमें मिलकर इसकी जांच कर रही हैं।

शुरूआती जांच में पता चला कि, जवानों को इंसास राइफल से गोलियां मारी गई हैं। पुलिस को मौके से इसके 19 खाली खोल बरामद हुए हैं। गोली मारने वाले 2 लोग सफेद कुर्ता-पायजामा पहनकर आए थे। मुंह ढका हुआ था। बठिंडा पुलिस ने इसमें टेरर एंगल से इनकार नहीं किया है। इस घटना से 2 दिन पहले यूनिट के गार्ड रूम से इंसास राइफल और गोलियां गायब हुई थी। पुलिस और आर्मी को इस राइफल का घटना में इस्तेमाल होने का शक है।

प्रदेश में साढ़े तीन सौ से ज्यादा नए करोना संक्रमित मिले बुधवार को

इनमें सर्वाधिक 82 मामले जयपुर में पाए गए हैं

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 12 अप्रेल। प्रदेश में करोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। राज्य में बुधवार को एक ही दिन में साढ़े तीन सौ से ज्यादा नए संक्रमित मिले हैं। वहीं एक मरीज की इस बीमारी से मौत भी हुई है। प्रदेश में फिलहाल साढ़े बारह सौ के करीब करोना के मरीजों का इलाज चल रहा है।

राज्य में दिनोंदिन करोना संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। 6 अप्रैल को इसके 100 केस सामने आए थे। जिसके बाद हर दिन तेज गति से मामले बढ़ने लगे हैं। बुधवार को 22 जिलों में 355 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले मंगलवार को 190 रोगी पाए गए थे। इधर आज राज्य में सबसे ज्यादा 82 नए संक्रमित जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा राजसमंद में 36, जोधपुर व अजमेर में 28-28, अलवर में 27, झालावाड़ 24, बीकानेर 21, उदयपुर 20, बूंदी 19, पाली 15, सवाई माधोपुर में 14, बांसवाड़ा व नागौर में 6-6, कोटा में 5, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में 4-4, प्रतापगढ़ में 3, चित्तौड़गढ़ व सिरोही में 2-2 तथा दौसा में 1 नया संक्रमित मिला है।

> ■ **राज्य में पिछले चौबीस घंटों में करोना से एक संक्रमित की मौत भी हुई है।**

प्रदेश में बुधवार को केवल 72 ही मरीज ठीक होने से एक्टिव केस बढ़कर 1245 हो गए हैं। इनमें सर्वाधिक सक्रिय 349 मरीज जयपुर में जिले में हैं। प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में करोना से जयपुर में एक संक्रमित की मौत भी हुई है। इसके साथ ही राज्य में इस बीमारी से अब तक 9671 लोगों मृत्यु हो चुकी है। हाल ही में करोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। इस महीने 12 दिन में 10 मौत हो चुकी है।

उधर चिकित्सा विशेषज्ञों ने करोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को भीड़भाड़ से बचने और मास्क पहने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि, करोना का नया वैरियंट ज्यादा घातक नहीं है, लेकिन पहले से बीमार लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है।

नीतीश कुमार व तेजस्वी यादव...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस ने बात की है, कुछ पार्टियों से हमने बात की है। उन्होंने आगे कहा कि शीघ्र ही एक और मीटिंग करने का निर्णय लिया गया है। कुमार ने मीडियाकर्मियों से कहा कि आपको मीटिंग की विस्तृत जानकारी दे दी जायेगी।

मीटिंग से पहले, कुमार ने आर.जे.डी. के पितामह लालू प्रसाद यादव से भेंट की, जो इस समय दिल्ली में अपनी पुत्री मीसा भारती के निवास पर ठहरे हुये हैं तथा उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया कि विपक्षी नेताओं ने जनता की आवाज उठाने तथा देश को नई दिशा देने का संकल्प लिया है। उन्होंने हिन्दी में ट्वीट किया, ''हम संविधान को संरक्षण प्रदान करेंगे तथा देश को बचायेंगे।'' खड़गे इससे पहले द्रमुक अध्यक्ष तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन तथा महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात कर चुके हैं।

जैसे-जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, विपक्षी दल सत्तासीन भाजपा का सामना करने के लिये नये समीकरणों की तलाश कर रही है।

लेकिन, जहाँ कुछ पार्टियों ने विपक्षी मोर्चे में शामिल होने के प्रश्न पर अपना रूख स्पष्ट कर दिया है, जबकि कुछ अन्य दलों ने मिश्रित संकेत दिये है।

उदाहरण के लिये, तृणमूल कांग्रेस ने शुरु में घोषणा की थी कि वह लोकसभा चुनाव अकेली ही लड़ेगी। पार्टी प्रमुख तथा बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह बयान उपचुनाव में उनकी पार्टी की हार के बाद दिया था। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उनकी पार्टी की पराजय वामपंथियों, कांग्रेस तथा भाजपा के बीच बनी समझबूझ का परिणाम था।

लेकिन जब राहुल गांधी की ''मोदी सरनेम'' वाली टिप्पणी को लेकर दायर किये गये मानहानि के केस में, उन्हें मिली सजा के बाद, राहुल गांधी को सांसद के रूप में डिस्क्वालिफाइड घोषित कर दिया गया, उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि तृणमूल कांग्रेस ने अपना पूर्व विचार बदल लिया है। इस घटना के शीघ्र बाद ही, बनर्जी ने विपक्षी दलों की एक मीटिंग बुलाई थी, ताकि संगठित होकर भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जा सके।

एक और प्रमुख विपक्षी दल, जिसने किसी मोर्चे में शामिल होने के बारे में अपना रूख अभी स्पष्ट नहीं किया है, आम आदमी पार्टी (आप) है। आप को अभी-अभी राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है तथा दिल्ली एवं पंजाब में उसकी सरकारे हैं। इस महीने के शुरु में, मीडिया से बात करते हुये, पार्टी नेता तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने कहा था कि जनता की एकता, न कि विपक्ष की एकता महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर पार्टियाँ कहती हैं कि वे किसी को हराने के लिए एक हो गई हैं, तो लोग इसे पसंद नहीं करते।

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चन्द्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति ने भी विपक्षी मोर्चे के गठन की दिशा में कदम उठाया है लेकिन वे नहीं चाहते कि इसमें कांग्रेस हो।

एक विपक्षी नता ने कहा कि हालांकि भाजपा तथा मीडिया का एक वर्ग इस प्रकार के प्रयासों को सिर्फ ''दिवास्वप्न'' (पाइपड्रीम) बताकर खारिज कर रहा है, लेकिन तकरीबन सभी विपक्षी दल एक संगठित मोर्चे की जबरदस्त जरूरत महसूस कर रहे हैं तथा सभी दल मोदी सरकार की प्रचंड राजनैतिक शैली से आतंकित होने लगे हैं। उक्त नेता ने कहा कि आज का निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है।

कर्नाटक के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

देने से इन्कार कर दिया तो वह पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की उपस्थिति में बुधवार को भाजपा में शामिल हो गई।

उन्होंने बैंगलोर के भाजपा मुख्यालय पर पार्टी में औपचारिक रुप से शामिल होने के बाद मीडिया कर्मियों को बताया कि ''मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस मेरी योग्यता को ध्यान में रखकर मुझे टिकट देगी, लेकिन मुझे अवसर नहीं दिया गया। भाजपा ने मेरा तहेदिल से स्वागत किया और मैं पार्टी के लिए काम करूंगी। ए.के. एंटनी की तरह ही राजनन्दिनी के पिता कोगडु थिमप्पा ने अपनी पुत्री के निर्णय पर निराशा प्रकट की। उन्होंने कहा कि ''मैंने आज यह खबर सुनी। मुझे उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके पीछे जरुर कोई ना कोई बात होगी। यह भाजपा नेता हर्तालु हलप्पा की चालबाजी हो सकती है। मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। मैं हमेशा कांग्रेस के पक्ष में रहूंगा और पार्टी के लिए काम करूंगा।

गहलोत ने सारे...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है तथा सूत्रों के अनुसार उन्होंने इस पत्र का मसौदा अपनी मर्जी से ही तैयार किया। उन्हें ऐसा करने के लिए किसी ने नहीं कहा था।

लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें थोड़ी समझ आ गई है या शायद राहुल गांधी ने उन पर अपना गुस्सा उतारा है। आज उन्होंने गहलोत और पायलट दोनों को पार्टी की सम्पत्ति बताया। इस शृंखला की तीसरी कड़ी हैं पवन खेड़ा, जो कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रभारी हैं।

वह भी गहलोत के बड़े भक्त हैं तथा वह गहलोत की प्रशंसा करने और सचिन को निशाना बनाने के लिए प्रेस कांफ्रेंसेज़ के आयोजन में कोई कमी नहीं रखते।

कांग्रेस पार्टी में जो भी कुछ चल रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे उसे लेकर एक मूक दर्शक बने हुए हैं, जबकि गांधी परिवार के सदस्यों ने तो इस संबंध में अब तक अपनी कोई प्रतिक्रिया ही व्यक्त नहीं की है।

सूत्र बताते हैं कि सचिन पायलट दिल्ली में हैं और वह शुक्रवार को राजस्थान आएंगे, तब तक वह स्थिति को देख रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं।

स्वयं के खिलाफ चल रहे सभी षड़यंत्रों के प्रति पायलट बेफिक्र प्रतीत होते हैं और बताया जाता है कि वे पुनः एक वृहद जनसम्पर्क अभियान शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें जयपुर ग्रामीण भी शामिल है और इसकी शुरूआत 17 अप्रेल को झुंझूनूं से की जाएगी।

प्रियंका गांधी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अटकलें हैं कि पायलट रंधावा व अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मिल सकते हैं पर अभी तक सूत्रों का यही कहना है कि ऐसी कोई मीटिंग अधिसूचित नहीं है।

पार्टी रंधावा की इस घोषणा के साथ खड़ी है कि पायलट अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पार्टी विरोधी गतिविधि है। उन्हें पार्टी के भीतर बात करनी चाहिए थी। इसी बीच खड़गे ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पायलट द्वारा भ्रष्टाचार के मसले पर गत वर्ष भेजे गए दो पत्रों पर चर्चा के लिए बुलाया गया है। वे पायलट से भी पत्र मांग सकते थे पर वे इतने नाराज हैं कि उन्होंने उनसे कोई भी दस्तावेज मांगना जरुरी नहीं समझा।

राहुल गांधी नीतीश कुमार से वार्ता के लिए खड़गे के आवास गए थे पर सूत्रों ने बताया कि उन्होंने राजस्थान मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहा। समझा जाता है कि उन्होंने अपनी बहन और ए.आई.सी.सी. महासचिव प्रियंका गांधी से मामले को हैंडल करने को कहा है क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुकी हैं।

पायलट-गहलोत...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फोकस पार्टी को मजबूत करने पर है पर इस पर भी है कि बतौर सरकार हम उन नीतियों का क्रियान्वयन करे जिनका जनता ने स्वागत किया है ताकि राजस्थान जहां कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, वहां हमें पुनः जनादेश मिले। आपके सवाल का मैंने जवाब दे दिया है। हम कृतसंकल्प हैं। हमारे लिए राष्ट्रीय लक्ष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी के लिए कांग्रेस प्रयास कर रही है।

नीतीश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अपना वर्चस्व बनाए रखने की कोशिश करेगी। पर यह विचार कुमार और तेजस्वी दोनों अनुकुल है। कुमार अपने राजनीतिक करियर के अंतिम पड़ाव पर हैं और बिहार में उनका चुनावी प्रभाव भी कम होता जा रहा है।

विपक्षी गठबंधन का संयोजक बन कर दिल्ली जाने का उनका इरादा तेजस्वी का रास्ता साफ करेगा क्योंकि तेजस्वी किसी भी उचित समय पर बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं।

इस प्रस्ताव को स्वीकार करना कांग्रेस के लिए फायदा और नुकसान दोनों ही है। किसी गैर कांग्रेसी नेता के नेतृत्व वाले गठबंधन के एक घटक दल के रूप में राहुल गांधी उस राजनीतिक बढ़त को खो देंगे जो उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद हासिल की थी।

वह बढ़त यह थी उन्हें भाजपा के खिलाफ संघर्ष में विपक्ष के कई नेताओं का प्राप्त होगा।

भाजपा ने एन्टी इन्क्म्बैन्सी से निपटने के लिये वही...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पार्टी ने विधायकों की जीतने की संभावना को लेकर कराया था।

जिन विधायकों को टिकट नहीं दिये गये हैं, उनमें एक बड़ा नाम कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर का भी है, जो एक वरिष्ठ लिंगायत नेता हैं। भाजपा को वर्तमान स्थिति तक लाने का श्रेय बी.एस. येद्दियुरप्पा के साथ उनको भी जाता है। साफ-स्वच्छ छवि वाला यह पुराना नेता विधानसभा के लिये छः बार निर्वाचित हो चुका है। शेट्टर ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, वे चुनाव तो लड़ेंगे। ऐसी आशंका है कि जिन लोगों के टिकट काटे गये हैं, वे कांग्रेस या जे.डी. (एस.) की मदद कर सकते हैं क्योंकि ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि वे भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार के पक्ष में काम नहीं करें।

इस समय कांग्रेस तथा जे.डी. (एस.) भाजपा के घटनाक्रम को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, जबकि शेष टिकटों को अंतिम रूप देने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि टिकट तो उसे देने ही हैं। कांग्रेस ने 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 166 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है लेकिन कांग्रेस भी विद्रोहियों की समस्या से घिरी हुई है क्योंकि कुछ कांग्रेसजनों, जिन्हें टिकट नहीं दिये गये हैं, ने धमकी दे दी है कि वे निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे तथा पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों की पराजय सुनिश्चित करेंगे।

लेकिन इस प्रकार का विरोध भाजपा में ज्यादा है लेकिन भाजपा समर्थकों को विश्वास है कि सत्ता-विरोधी लहर बेअसर हो जायेगी तथा पार्टी सत्ता में लौट आयेगी। और इस जीत का कारण होंगे- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नेतृत्व तथा, राज्य तथा केन्द्र की डबल इंजन सरकारों की शासन-व्यवस्था। भाजपा का हर नेता तथा कार्यकर्ता इस चीज को घर-घर पहुँचा रहा है।

इस बीच, ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि येद्दियुरप्पा, जिनके पुत्र को तो चुनाव लड़ने के लिये टिकट दे दिया गया है, लेकिन वे इस बात को लेकर अप्रसन्न बताये जाते हैं कि उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिये गये। वे यह कहने के बाद, अपने घर लौट गये कि उनके सुझाव स्वीकार कर लिये गये हैं किन्तु वे चुनाव में कोई खास योगदान नहीं दे पायेंगे।

राजनैतिक हल्कों में इसका अर्थ यह निकाला जा रहा है कि भाजपा के इस पुराने दिग्गज, जिसने दक्षिण भारत में प्रवेश के मामले में पार्टी की बहुत मदद की थी, की पार्टी के अन्दर अनदेखी की जा रही है तथा उनकी यह उपेक्षा पार्टी को महँगी पड़ सकती है।

हालाँकि एक अन्य पुराने नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने घोषणा तो यह की है कि वे चुनावी राजनीति से हट रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि उन्हें इस बात के पर्याप्त संकेत मिल गये हैं कि उन्हें टिकट नहीं दिया जायेगा। उन्होंने, टिकट नहीं मिलने की बजाय, इस्तीफा देना श्रेयस्कर समझा तथा पूरे प्रचार-प्रसार के साथ, अपना त्याग पत्र पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के पास भेज दिया।

उन्होंने अपने त्याग पत्र में कहा है, ''मैं चुनावी राजनीति छोड़ रहा हूँ। ....पार्टी ने पिछले 40 सालों में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दीं। मैं बूथ-प्रभारी से पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पद तक पहुँचा। मुझे उपमुख्यमंत्री बनने का भी गौरव मिला।'' कांग्रेस ने भाजपा पर कटाक्ष किया है कि उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही, भाजपा के विकेट गिरने लगे हैं।

लेकिन भाजपा का कहना है कि ईश्वरप्पा का चुनाव न लड़ने का निर्णय उनका निजी निर्णय है। मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा है, ''ईश्वरप्पा इस बारे में हम लोगों से पिछले कुछ महीनों से बात कर रहे थे, लेकिन हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। आज उन्होंने हाई कमान को त्याग पत्र भेज दिया है तथा हमें इस (उनके निर्णय) का सम्मान करना चाहिये।''

भाजपा की इस सूची का आधार पार्टी द्वारा कराया गया वह व्यापक सर्वे रहा है जिसमें प्रत्येक विधायक के जीतने की संभावनाओं को परखा गया था। प्रत्येक सीट तथा उम्मीदवार के लिये, पार्टी ने 300 पूर्व तथा वर्तमान पार्टी पदाधिकारियों, सरपंचों तथा जिला परिषद प्रमुखों से बातचीत की थी तथा उम्मीदवार के विषय में उनकी पसंद लिखित में ले ली गई थी।

कर्नाटक के लिये भाजपा के चुनाव-प्रभारी धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में 25000 कार्यकर्ताओं से परामर्श किया गया था। उसके बाद इस सूची की संवीक्षा की गई थी तथा उसके बाद पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने उसे क्लिअरेंस दी थी।

भाजपा अध्यक्ष नड्डा ने राष्ट्रीय संगठन सचिव बी.एल. संतोष, सह-प्रभारीगण के अन्नामलाई एवं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया एवं महासचिव अरूण सिंह तथा प्रधान के साथ विस्तृत चर्चाएं की थीं। अंत में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका अनुमोदन किया था।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908